

एनईपी 2020 के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास

Dr. Nehal Parsai

Research Scholar, Devi Ahilya, University, Indore

सार

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शुरुआत भारतीय शिक्षा प्रणाली में, विशेष रूप से व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक है। नीति रोजगार क्षमता बढ़ाने, शैक्षणिक ज्ञान और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच अंतर को कम करने और छात्रों के बीच व्यावहारिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है। एनईपी 2020 के तहत, व्यावसायिक शिक्षा को स्कूल स्तर से शुरू करने की योजना है, जिसकी शुरुआत ग्रेड 6 से होगी, जिसमें इंटरशिप, व्यावहारिक प्रशिक्षण और विभिन्न व्यापारों और व्यवसायों के संपर्क के अवसर होंगे। नीति का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली में कम से कम 50 प्रतिशत शिक्षार्थियों को 2025 तक व्यावसायिक शिक्षा से अवगत कराया जाए। यह बहु-विषयक शिक्षा, पाठ्यक्रम चयन में लचीलेपन और उद्योग भागीदारों, कौशल विकास संस्थानों और स्थानीय कारीगरों के साथ सहयोग को बढ़ावा देता है। यह पहल कुशल और नौकरी के लिए तैयार कार्यबल बनाने के लिए कौशल भारत मिशन जैसे राष्ट्रीय कौशल मिशन और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम जैसे संस्थागत ढांचे के साथ भी संरेखित है। अनुभवात्मक शिक्षा, इंटरशिप और योग्यता-आधारित शिक्षा पर जोर देकर, एनईपी 2020 व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच पारंपरिक विभाजन को खत्म करने का प्रयास करता है। यह नीति आजीवन सीखने, उद्यमिता और नवाचार को प्रोत्साहित करती है, जिससे आर्थिक विकास और सामाजिक विकास में योगदान मिलता है। कुल मिलाकर, एनईपी 2020 के तहत व्यावसायिक शिक्षा युवाओं को प्रासंगिक कौशल के साथ सशक्त बनाने, रोजगार के अवसरों को बढ़ाने और ज्ञान-आधारित और कौशल-संचालित अर्थव्यवस्था की ओर भारत के संक्रमण का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

मुख्य शब्द: NEP, 2020, अंतर्गत, व्यावसायिक, शिक्षा, कौशल

परिचय

शिक्षा किसी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समकालीन वैश्विक अर्थव्यवस्था में, कौशल-आधारित शिक्षा का महत्व काफी बढ़ गया है क्योंकि उद्योग और संगठन व्यावहारिक ज्ञान, तकनीकी क्षमता और समस्या-समाधान क्षमताओं से लैस कार्यबल की मांग करते हैं। भारत सहित कई देशों में पारंपरिक शिक्षा प्रणालियों ने बड़े पैमाने पर सैद्धांतिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया है, अक्सर व्यावसायिक और कौशल-उन्मुख प्रशिक्षण की उपेक्षा की जाती है। इस असंतुलन ने अकादमिक शिक्षा और श्रम बाजार के लिए आवश्यक कौशल के बीच एक अंतर पैदा कर दिया है। इस चुनौती को पहचानते हुए, भारत सरकार ने शिक्षा प्रणाली में सुधार करने और इसे 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था की जरूरतों के साथ संरेखित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पेश की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर इसका मजबूत जोर है। इस नीति का उद्देश्य स्कूल स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक

व्यावसायिक प्रशिक्षण को मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली में एकीकृत करना है। इसका प्रस्ताव है कि व्यावसायिक प्रदर्शन प्रारंभिक चरण में शुरू होना चाहिए, विशेष रूप से ग्रेड 6 से, इंटरनशिप, व्यावहारिक परियोजनाओं और स्थानीय कारीगरों और पेशेवरों के साथ बातचीत जैसी गतिविधियों के माध्यम से। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य छात्रों को व्यावहारिक कौशल विकसित करने, श्रम की गरिमा को समझने और पारंपरिक शैक्षणिक व्यवसायों से परे विभिन्न कैरियर मार्गों का पता लगाने में मदद करना है।

यह नीति भारत में व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे सामाजिक कलंक को दूर करने का भी प्रयास करती है। ऐतिहासिक रूप से, व्यावसायिक प्रशिक्षण को अक्सर अकादमिक शिक्षा की तुलना में कम प्रतिष्ठित माना जाता है, जिसने कई छात्रों को कौशल-आधारित करियर बनाने से हतोत्साहित किया है। व्यावसायिक विषयों को नियमित पाठ्यक्रम में एकीकृत करके और बहु-विषयक शिक्षा को बढ़ावा देकर, नीति शैक्षणिक और व्यावसायिक धाराओं के बीच समानता बनाने का प्रयास करती है। इसके अलावा, इस पहल का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वर्ष 2025 तक कम से कम 50 प्रतिशत शिक्षार्थी व्यावसायिक शिक्षा से परिचित हों, जिससे कुशल मानव संसाधनों का एक बड़ा पूल तैयार हो सके। इसके अलावा, नीति व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता और प्रासंगिकता बढ़ाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों, उद्योगों और कौशल विकास संगठनों के बीच सहयोग पर जोर देती है। कौशल भारत मिशन जैसे कार्यक्रम और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के प्रयास देश भर में कौशल विकास के उद्देश्यों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन पहलों का उद्देश्य लाखों युवाओं को प्रशिक्षण, प्रमाणन और रोजगार के अवसर प्रदान करना है, जिससे भारत के कार्यबल को मजबूत किया जा सके और सतत आर्थिक विकास का समर्थन किया जा सके। इस प्रकार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम का प्रतिनिधित्व करता है जो समावेशी, लचीली और आधुनिक अर्थव्यवस्था की मांगों के अनुरूप है। व्यावहारिक शिक्षा, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देकर, नीति का उद्देश्य युवाओं को रोजगार, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक कौशल के साथ सशक्त बनाना है।

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास की अवधारणा

व्यावसायिक शिक्षा शिक्षा के एक ऐसे रूप को संदर्भित करती है जो विशिष्ट व्यवसायों और उद्योगों के लिए आवश्यक व्यावहारिक कौशल, तकनीकी ज्ञान और दक्षता विकसित करने पर केंद्रित है। पारंपरिक शैक्षणिक शिक्षा के विपरीत, जो मुख्य रूप से सैद्धांतिक शिक्षा पर जोर देती है, व्यावसायिक शिक्षा व्यावहारिक प्रशिक्षण और अनुभवात्मक सीखने के अवसर प्रदान करती है जो व्यक्तियों को रोजगार और स्वरोजगार के लिए तैयार करती है। आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में, व्यावसायिक शिक्षा उत्पादकता बढ़ाने, बेरोजगारी कम करने और तेजी से बदलते उद्योगों की मांगों को पूरा करने में सक्षम कुशल कार्यबल तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए औपचारिक शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक प्रशिक्षण का एकीकरण कई देशों में एक महत्वपूर्ण नीति प्राथमिकता बन गया है। भारत में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से इस उद्देश्य पर दृढ़ता से जोर दिया गया है, जो अधिक लचीली और रोजगार-उन्मुख शिक्षा प्रणाली (शिक्षा मंत्रालय, 2020) बनाने के लिए मुख्यधारा की शिक्षा के साथ कौशल विकास को एकीकृत करना चाहता है।

एनईपी 2020 में व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत व्यावसायिक शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य अकादमिक शिक्षा और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच अंतर को पाटना है। नीति मानती है कि औपचारिक शैक्षणिक योग्यता होने के बावजूद

भारतीय युवाओं के एक बड़े हिस्से में नौकरी के लिए तैयार कौशल की कमी है। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए, एनईपी 2020 का लक्ष्य ग्रेड 6 से शुरू होने वाले स्कूल स्तर के छात्रों को इंटरनशिप, व्यावहारिक प्रशिक्षण और कुशल पेशेवरों के साथ बातचीत जैसी गतिविधियों के माध्यम से व्यावसायिक अनुभव प्रदान करना है। नीति का लक्ष्य यह भी सुनिश्चित करना है कि स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में कम से कम 50 प्रतिशत शिक्षार्थियों को 2025 तक व्यावसायिक शिक्षा का लाभ मिले। इस पहल से रोजगार क्षमता में सुधार, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और छात्रों को विविध कैरियर मार्ग अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की उम्मीद है (शिक्षा मंत्रालय, 2020)।

स्कूली पाठ्यक्रम के साथ व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण

नियमित स्कूल पाठ्यक्रम के साथ व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण एनईपी 2020 में प्रस्तावित प्रमुख सुधारों में से एक है। नीति अनुभवात्मक शिक्षा, परियोजना-आधारित शिक्षा और ज्ञान के वास्तविक जीवन अनुप्रयोगों पर जोर देती है। छात्रों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए स्कूलों को स्थानीय उद्योगों, कारीगरों और व्यावसायिक संस्थानों के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इंटरनशिप और क्षेत्र-आधारित शिक्षा के माध्यम से, छात्र विभिन्न व्यवसायों की समझ हासिल करते हैं और टीम वर्क, संचार और समस्या-समाधान जैसे आवश्यक जीवन कौशल विकसित करते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल शिक्षा की प्रासंगिकता को बढ़ाता है बल्कि श्रम और कुशल व्यवसायों की गरिमा के प्रति सम्मान विकसित करने में भी मदद करता है। नीति में शिक्षा के बहु-विषयक ढांचे (शिक्षा मंत्रालय, 2020) के भीतर वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के रूप में व्यावसायिक विषयों को शामिल करने का भी प्रस्ताव है।

कौशल विकास में सरकारी पहल की भूमिका

व्यावसायिक शिक्षा के सफल कार्यान्वयन के लिए मजबूत संस्थागत समर्थन और राष्ट्रीय कौशल विकास पहल के साथ सहयोग की आवश्यकता है। भारत में, लाखों युवाओं को विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक कौशल में प्रशिक्षित करने के लिए कौशल भारत मिशन जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य उद्योग-प्रासंगिक प्रशिक्षण, प्रमाणन और रोजगार के अवसर प्रदान करना है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम जैसे संस्थान कौशल विकास कार्यक्रमों के समन्वय, प्रशिक्षण प्रदाताओं का समर्थन करने और उद्योगों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तरह की पहल व्यावसायिक प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और युवा लोगों की रोजगार क्षमता को बढ़ाकर एनईपी 2020 के उद्देश्यों को पूरा करती है (एनएसडीसी, 2021)।

आर्थिक विकास के लिए व्यावसायिक शिक्षा का महत्व

व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास का आर्थिक विकास और राष्ट्रीय विकास से गहरा संबंध है। एक कुशल कार्यबल उत्पादकता बढ़ाता है, नवाचार को बढ़ावा देता है और उद्योगों और सेवाओं के विस्तार का समर्थन करता है। भारत जैसे विकासशील देश में, जहां आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवाओं का है, जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन करने के लिए कौशल विकास आवश्यक है। छात्रों को तकनीकी और व्यावसायिक कौशल से लैस करके, व्यावसायिक शिक्षा बेरोजगारी को कम करने में मदद करती है और उद्यमिता को प्रोत्साहित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित सुधारों का उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम ज्ञान-संचालित और

कौशल-उन्मुख समाज बनाना है। इसलिए, व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत करना न केवल एक शैक्षिक सुधार है बल्कि सतत आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में एक रणनीतिक कदम भी है (शिक्षा मंत्रालय, 2020)।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्यों एवं सुझावों का अध्ययन - व्याख्या-

व्यावसायिक शिक्षा हमारे भारतीय शिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणादायक स्रोत है। भारतीय शिक्षा को सन्दर्भ को बदलने में व्यावसायिक शिक्षा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण का कार्यक्रम 1976 में आरम्भ किया गया। परन्तु शिक्षा के व्यावसायीकरण की योजना ने अभी गति नहीं पकड़ी है। इस धीमी प्रगति के बहुत से कारण हैं- जैसे अच्छी समन्वित प्रबन्ध पद्धति की कमी, व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त लोगों के लिए बेरोजगारी, माँग एवं आपूर्ति में सामंजस्य न होना, समाज द्वारा इस अवधारणा को स्वीकार करने की अनिच्छा, अतः व्यावसायिक शिक्षा पद्धति को सुदृढ़ बनाने के लिए तत्काल कदम उठाना अति आवश्यक है।

व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों को नियोजित तथा कार्यान्वित करने में किये जाने वाले विभिन्न कार्यों, उत्तर प्राथमिक, उत्तर माध्यमिक एवं उत्तर-उच्चतर माध्यमिक स्तरों में अपेक्षित परिवर्तनों के अनुरूप क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि एक प्रभावशाली प्रबन्धन पद्धति संगठित की जाये। व्यावसायिक शिक्षा छात्रों को प्रदान की जाने वाली वह शिक्षा है जिससे छात्र अपनी +2 की शिक्षा पूरी करने के बाद वास्तविक जीवन में प्रवेश के लिए तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किसी व्यवसाय या रोजगार को अपना सकें तथा धन अर्जित कर सकें। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक वृद्धि एवं उनके रोजगार में उन्नति के अवसरों की कमी। व्यावसायिक शिक्षा के विरुद्ध धारण किये गये पूर्वाग्रह तब तक दूर नहीं होंगे जब तक माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को लाभप्रद रोजगार के उचित अवसर अथवा शिक्षा व्यावसायिक या सामान्य कार्यक्रमों में आगे जाने की सुविधाएँ प्रदान नहीं की जायेंगी। ऐसे कार्यक्रमों में डिप्लोमा विशेष डिग्री पाठ्यक्रम, व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रमों को शामिल किया जा सकता है। इक्कीसवीं सदी में राष्ट्रों की प्रगति, विकास और साख का मूल आधार उनकी ज्ञान संपदा ही होगी। यह आधार जितना सशक्त, समेकित, जगह तथा परिवर्तनों के प्रति सतर्क और गतिशील होगा, राष्ट्र की प्रगति में नागरिकों की भागीदारी भी उतनी ही विस्तृत और सर्वव्यापी होगी। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए भारत की प्राथमिक आवश्यकता हर व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण तथा उपयोगी कौशलों की ग्राह्यता से परिपूर्ण शिक्षा पहुँचाने की होगी। ऐसे में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 देश के लिए सकारात्मक संभावनाओं के द्वार खोलती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के आधार सिद्धान्त का वर्णन शिक्षा के व्यापक एवं बहुआयामी महत्त्व को रेखांकित करता है। इसके अनुसार 'शैक्षिक प्रणाली का मुख्य उद्देश्य अच्छे इंसान का विकास करना है- जो तर्क संगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो, जिसमें करुणा एवं सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतना और रचनात्मक कल्पना शक्ति, नैतिक मूल्य और आधार हों। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादक लोगों को तैयार करना है, जो कि अपने संविधान द्वारा परिकल्पित समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान करें। इसमें आगे यह भी कहा गया है कि हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना होगा। निश्चित रूप से इस हेतु शिक्षकों और अभिभावकों को तैयार किया है। इस शिक्षा नीति का विजन भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है, जो राष्ट्र की शैक्षिक आवश्यकता और शिक्षा के समावेशी चरित को आगे बढ़ा सके। शिक्षा के अन्तर्गत उसकी सर्वसुलभता, सक्षमता निर्माण, कौशल विकास तथा गुणवत्ता का तत्त्व समाहित हो।

नई शिक्षा नीति-2020 में व्यावसायिक शिक्षा को ध्यान में रखते हुए निम्न प्रावधान किये गये हैं-

5 प्रतिशत से भी कम भारतीय कार्यबल ने औपचारिक अवकाश शिक्षा प्राप्त की है। इसलिए इस प्रतिशत को बढ़ाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा संरचना को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि एक राष्ट्र के रूप में हम अधिक उन्नत और विकासशील देशों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें और इसके लिए व्यावसायिक शिक्षा आवश्यक है।

चरणबद्ध तरीके से व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करना, जिसमें मध्य और माध्यमिक विद्यालय में कम उम्र में व्यावसायिक प्रदर्शन की शुरुआत शामिल है। (एनईपी पैरा 16.4)।

कक्षा 6 से शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा के प्रति जागरूक करने का प्रावधान किया गया है ताकि व्यवसाय के प्रति सही धारणा और दृष्टिकोण विकसित हो सके। आप कह सकते हैं कि यह व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ी सामाजिक स्थिति के पदानुक्रम को दूर करने के लिए किया गया प्रयास है।

द्वितीय 2025 तक, स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50 प्रतिशत शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव होगा, जिसके लिए लक्ष्य और समयसीमा के साथ एक स्पष्ट कार्य योजना विकसित की जाएगी (पैरा 16.5)। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए माध्यमिक शिक्षा संस्थान तकनीकी संस्थानों जैसे आईटीआई पॉलिटेक्निक, कुछ स्थानीय उद्योगों आदि के साथ सहयोग करेंगे। इन कदमों से छात्र व्यवसाय के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे और किसी विशेष व्यवसाय के प्रति अपने कौशल और रुचि विकसित करने में सक्षम होंगे और इसमें महारत हासिल कर सकेंगे।

श्लोक विद्या- यानी भारत में विकसित महत्वपूर्ण व्यावसायिक ज्ञान को व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में एकीकरण के माध्यम से छात्रों के लिए सुलभ बनाया जाएगा। (एनईपी पैरा 16.5)। हमारी संस्कृति से दिन-ब-दिन लुप्त होती जा रही लोकविद्या को कायम रखने के लिए विद्यार्थियों तक पहुंचाने की जरूरत है और इसी उद्देश्य से विभिन्न स्थानीय विशेषज्ञों की पहचान की जाएगी और उनके तहत विद्यार्थियों को इंटरनशिप प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें इंटरनशिप कार्यक्रम का औपचारिक और अनौपचारिक तरीका होगा। स्थानीय व्यावसायिक शिल्पों की पहचान की जाएगी और छात्र उनके शिल्पों का पता लगाएंगे और इन स्वदेशी प्रथाओं के बारे में इंटरनशिप आयोजित की जाएगी। उनकी कई प्रथाएं हैं जो अनोखी हैं और केवल भारत में ही प्रचलित हैं। इन कलाओं और प्रथाओं को संरक्षित करने के प्रयास किए जाने चाहिए और इसमें कम उम्र में इंटरनशिप मददगार हो सकती है।

व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम को केवल नियमित स्कूली शिक्षा तक सीमित नहीं किया जा सकता है, बल्कि ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पेशकश भी की जानी चाहिए ताकि प्रत्येक शिक्षार्थी अपने कौशल विकसित कर सकें और अपने वांछित लक्ष्यों को पूरा कर सकें।

व्यावसायिक शिक्षा को अगले दशक में चरणबद्ध तरीके से सभी स्कूल और उच्च शिक्षा संस्थानों में एकीकृत किया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा के लिए फोकस क्षेत्रों को कौशल अंतर विश्लेषण और स्थानीय अवसरों के मानचित्रण के आधार पर चुना जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय का नाम बदला गया) इस प्रयास की निगरानी के लिए व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए एक राष्ट्रीय समिति (एनसीआईवीई) का गठन करेगा, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा के विशेषज्ञ और उद्योग के सहयोग से सभी मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। (एनईपी पैरा 16.6)। छात्रों को सूचित करियर विकल्प चुनने में मार्गदर्शन के लिए आठवीं कक्षा में व्यावसायिक रुचि सूची और दसवीं कक्षा में कौशल आधारित योग्यता परीक्षण (एसबीएटी) की शुरुआत। इससे छात्रों को सही करियर विकल्प चुनने में मदद मिलेगी और उन्हें उनके कौशल और रुचि के अनुसार निर्देशित किया जाएगा।

निष्कर्ष

व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास आधुनिक शिक्षा प्रणालियों के आवश्यक घटकों के रूप में उभरे हैं, खासकर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में जहां रोजगार सृजन और कार्यबल की तैयारी महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कार्यान्वयन व्यावहारिक शिक्षा, कौशल अधिग्रहण और उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण पर जोर देकर भारतीय शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार का प्रतिनिधित्व करता है। व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा के शैक्षणिक पाठ्यक्रम के साथ एकीकृत करके, नीति सैद्धांतिक शिक्षा और श्रम बाजार में आवश्यक व्यावहारिक कौशल के बीच लंबे समय से चली आ रही खाई को पाटने का प्रयास करती है। स्कूल स्तर से व्यावसायिक प्रशिक्षण, इंटरशिप और अनुभवात्मक शिक्षा के शुरुआती प्रदर्शन पर नीति का फोकस छात्रों की दक्षता, रचनात्मकता और समस्या-समाधान क्षमताओं को विकसित करना है। इसके अलावा, उद्योग भागीदारों और कौशल विकास संगठनों के साथ सहयोग यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षार्थियों को प्रदान किया गया प्रशिक्षण उभरती अर्थव्यवस्था की जरूरतों के लिए प्रासंगिक बना रहे। कौशल भारत मिशन जैसी राष्ट्रीय पहल और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम जैसे संस्थानों का समर्थन व्यावसायिक शिक्षा के पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करता है और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाता है। इसके अलावा, एनईपी 2020 श्रम की गरिमा को बढ़ावा देने और लचीले शैक्षिक मार्ग प्रदान करके पारंपरिक रूप से व्यावसायिक करियर से जुड़े सामाजिक कलंक को दूर करने का प्रयास करता है। यह दृष्टिकोण छात्रों को उद्यमिता और तकनीकी व्यवसायों सहित विविध कैरियर विकल्पों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे आर्थिक विकास और सामाजिक विकास में योगदान मिलता है। 2025 तक कम से कम 50 प्रतिशत शिक्षार्थियों को व्यावसायिक अनुभव प्रदान करने के लक्ष्य के साथ, यह नीति एक कुशल, नवोन्वेषी और आत्मनिर्भर कार्यबल के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। निष्कर्षतः, एनईपी 2020 के तहत व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास एक समावेशी, लचीली और रोजगारोन्मुख शिक्षा प्रणाली को आकार देने में परिवर्तनकारी भूमिका निभाते हैं। यदि प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो इन सुधारों में भारत के युवाओं को सशक्त बनाने, राष्ट्रीय उत्पादकता बढ़ाने और ज्ञान-आधारित और कौशल-संचालित अर्थव्यवस्था की ओर देश के परिवर्तन का समर्थन करने की क्षमता है।

संदर्भ

1. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. (2020). नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार.
2. नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. (2021). भारत में स्किल डेवलपमेंट की पहल और प्रोग्राम. नई दिल्ली: NSDC.
3. स्किल इंडिया मिशन. (2015). स्किल इंडिया: भारत को एक स्किल्ड देश में बदलना. नई दिल्ली: भारत सरकार.
4. यूनेस्को. (2016). टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग (TVET) 2016-2021 के लिए स्ट्रेटेजी. पेरिस: यूनेस्को.
5. वर्ल्ड बैंक. (2019). काम का बदलता नेचर और स्किल डेवलपमेंट. वाशिंगटन, DC: वर्ल्ड बैंक.
6. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइज़ेशन. (2018). 21वीं सदी में स्किल और एम्प्लॉयबिलिटी. जिनेवा: ILO.
7. अजय कुरियन और सुदीप बी चंद्रमना, साइटेड इन सिंह, बिरेंद्र एवं देवी, कुकन (2022), उच्च शिक्षा के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च एण्ड एनॉलिटिकल रिव्यूस, वॉ० 9, इश्यू-1, पृ० 17-20

8. कुमार, प्रकाश: 21वीं सदी की मांग पूरी करेगी नई शिक्षा नीति आउटलुक हिंदी, 24 अगस्त 2020।
9. कुरैन, अजय, चन्द्रमना, बी, सुदीप (दिसंबर 2020). इंपैक्ट आफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑन हायर एजुकेशन,
10. सिंह, रेनू एवं सिंह, नागेन्द्र कुमार (2023). राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौशल विकास, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी-2020 : इम्पलबिल्टी एण्ड एसेसबिल्टी, प्रयागराज : चन्द्रा ब्रदर्स।
11. मिश्र, आलोक कुमार (2023). मनुस्मृति में निहित आत्मनिर्भरता एवं स्वावलम्बन शिक्षा का नयी शिक्षा नीति-2020 में समालोचनात्मक अध्ययन, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी-2020: इम्पलबिल्टी एण्ड एसेसबिल्टी, प्रयागराज चन्द्रा ब्रदर्स।